

भारत सरकार
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 496
02/12/2021 को उत्तर दिए जाने के लिए

वैश्विक तापमान में वृद्धि (ग्लोबल वॉर्मिंग) के प्रभाव संबंधी अध्ययन

496. श्री सैयद जफर इस्लाम

क्या पृथ्वी विज्ञान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने ग्लोबल वॉर्मिंग के कारण बढ़ते तापमान और घटते जल स्रोत के संबंध में विस्तृत अध्ययन कराया है अथवा करने का विचार रखती है; और
- (ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में घटते जलस्रोत और घटते भू-जलस्तर हेतु कार्य योजना सहित, उक्त प्रयोजन हेतु प्रयोग में लाए जाने के लिए प्रस्तावित आधुनिक प्रौद्योगिकियाँ क्या हैं ?

उत्तर

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(डॉ. जितेंद्र सिंह)

- (क)-(ख) जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के तहत केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी), निगरानी कुओं के नेटवर्क के माध्यम से क्षेत्रीय स्तर पर पूरे देश में भूजल स्तर की समय-समय पर निगरानी कर रहा है।

देश के गतिशील भूजल संसाधनों का भी समय-समय पर केंद्रीय भूजल बोर्ड और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से मूल्यांकन भी किया जा रहा है। वर्ष 2017 के आकलन के अनुसार, देश में कुल 6881 मूल्यांकन इकाइयों (ब्लॉक/तालुका/मंडल/वाटरशेड/फिरका) में से 17 राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों में 1186 इकाइयों को 'अति-शोषित' के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जहां कुल वर्तमान वार्षिक भू-जल निकासी वार्षिक निष्कर्षण भूजल संसाधन से अधिक है।

केंद्रीय भूजल बोर्ड भूजल संसाधनों के सतत विकास की सुविधा के लिए जलभृतों के मानचित्रण, उनके लक्षण-वर्णन और जलभृत प्रबंधन योजनाओं के विकास के लिए "नेशनल एक्वीफर मैपिंग एंड मैनेजमेंट (एनएक्यूआईएम)" का एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है। अब तक लगभग 11 लाख वर्ग किमी को कवर किया जा चुका है। जलभृत मानचित्र और प्रबंधन योजनाओं को संबंधित राज्य सरकार की एजेंसियों के साथ साझा किया गया है। हितधारकों के लाभ के लिए जलभृत प्रबंधन योजनाओं के सिद्धांतों के प्रसार के लिए जमीनी स्तर पर जन संपर्क कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) के अनुसंधान एवं विकास प्रभाग, परियोजना योजना विंग, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण विंग ने कुछ प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों को जल संसाधनों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर अध्ययन का उत्तरदायित्व सौंपा है। भारतीय राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन समिति (आईएनसीसीसी) की देखरेख में अध्ययन कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

क्र. सं.	अध्ययन का नाम	संस्थान का नाम
1	महानदी बेसिन के जल-मौसम विज्ञान प्रक्रियाओं और जल संसाधनों पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव आकलन	आईआईएससी बेंगलोर और आईआईटी भुवनेश्वर
2	राजस्थान के लिए जलवायु परिवर्तन प्रभाव अध्ययन (अंतर्देशीय जल निकासी और माही बेसिन का क्षेत्र)	एमएनआईटी जयपुर, आईआईटी दिल्ली और केंद्रीय विश्वविद्यालय, राजस्थान
3	लुनी नदी बेसिन जलवायु और जल विज्ञान मॉडलिंग	आईआईटी जोधपुर
4	तापी बेसिन के जल संसाधनों पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव	एसवीएनआईटी सूरत, एमएनआईटी जयपुर, और एम.ए.एन.आई.टी. भोपाल
5	साबरमती बेसिन के जल संसाधनों पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव	आईआईटी गांधीनगर और एसवीएनआईटी सूरत
6	तादरी से कन्याकुमारी तक नदी घाटियों में जल संसाधनों पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव	आईआईटी मुंबई, एनआईटी सुरकथल और सीडब्ल्यूआरडीएम कोझीकोड
7	सुवर्णरेखा बेसिन में स्थानिक और अस्थायी जल उपलब्धता पर जलवायु परिवर्तन और भूमि उपयोग/भूमि आवरण परिवर्तन के प्रभाव	आईआईटी खड़गपुर

केंद्रीय भूजल बोर्ड ने उत्तर प्रदेश राज्य सहित देश के सभी राज्यों के लिए NAQUIM रिपोर्ट तैयार की है जिसमें लगभग 17 जिलों के लिए जानकारी उपलब्ध है और रिपोर्ट <http://cgwb.gov.in/AQM/UP%20Reportdistrict.html> पर उपलब्ध है।

इसके अलावा केंद्रीय भूजल बोर्ड ने "भारत में भूजल के कृत्रिम रिचार्ज के लिए मास्टर प्लान" (<http://cgwb.gov.in/documents/masterplan-2013.pdf>) और "भूजल के कृत्रिम रिचार्ज पर मैनुअल" (<http://cgwb.gov.in/documents/Manual-Artificial-Recharge.pdf>) प्रकाशित किया जिसमें विभिन्न नई तकनीकों पर चर्चा की जाती है।
